भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1626
बुधवार, 10 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना

1626. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:
सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में 'ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (जीकेएमएस)' योजना के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है और वर्तमान में कार्यरत कृषि-मौसम विज्ञान क्षेत्र इकाइयों (एएमएफयू) और जिला कृषि-मौसम परामर्श केंद्रों (डीएएमयू) की संख्या कितनी है;

(ख) क्या नंदुरबार, सोलापुर और सांगली जिले जीकेएमएस तंत्र के अंतर्गत आते हैं और यदि हाँ, तो जिले में किसानों के लिए कृषि-मौसम परामर्शों के प्रसार की आवृत्ति और रीति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में किसानों के लिए फसल उत्पादकता, आदान लागत में कमी और मौसम जोखिम न्यूनीकरण पर जीकेएमएस परामर्शों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) जीकेएमएस के अंतर्गत कृषि- मौसम विज्ञान पूर्वानुमानों की सटीकता, स्थानीयकरण और डिजिटल पहुँच में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार का पश्चिमी महाराष्ट्र में व्यापक किसान पहुंच के लिए जीकेएमएस डेटा को किसान कॉल सेंटर, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और मोबाइल-आधारित प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, (जीकेएमएस) योजना संचालित करता है। इसके तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयूएस), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) आदि के सहयोग से मौसम पूर्वानुमान पर आधारित प्रचालनात्मक कृषि मौसम विज्ञान परामर्शी सेवाएं (एएएस)प्रदान की जाती हैं।

महाराष्ट्र में 9 कृषि मौसम विज्ञान क्षेत्र इकाइयां (एएमएफयू) हैं, यथा अकोला, दापोली, इगतपुरी, कोल्हापुर, मुलदे, परभणी, पुणे, राहुरी और सिंदेवाही, जो अलग-अलग राज्य कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में स्थित हैं और अभी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना (जीकेएमएस) के तहत प्रचालनरत हैं। कृषि मौसम विज्ञान क्षेत्र इकाइयां महाराष्ट्र के सभी खेती के लिए महत्वपूर्ण जिलों के लिए अंग्रेजी और मराठी भाषा में जिला-स्तरीय कृषि मौसम विज्ञान परामर्शी सेवा बुलेटिन तैयार कर रहे हैं और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड के तहत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट आदि जैसे मल्टीचैनल प्रसारण प्रणाली के माध्यम से किसानों तक कृषि मौसम विज्ञान परामर्शी सेवाएं पहुंचाने में भी शामिल हैं, जिसमें एसएमएस भी शामिल है।

इसके अलावा, ये इकाइयां दूसरी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा गतिविधियां भी करती हैं, जैसे कि गंभीर मौसम की चेतावनियों के दौरान कृषि के लिए प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान (IBFs) और उपयुक्त परामर्श तैयार करना और प्रसारित करना, जिसमें सभी किसान परिवारों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए उपलब्ध प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है।

(ख) जी हाँ। नंदुरबार, सोलापुर और सांगली ज़िले ग्रामीण कृषि मौसम सेवा नेटवर्क के तहत आते हैं और इन ज़िलों के लिए हर सप्ताह दो बार (हर मंगलवार और शुक्रवार) अंग्रेजी और मराठी दोनों भाषाओं में कृषि मौसम परामर्शिकाएँ जारी की जा रही हैं। ये कृषि मौसम परामर्शिकाएँ किसानों तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स और WhatsApp, Facebook जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कई तरीकों से पहुँचाई जाती हैं।

(ग) महाराष्ट्र में किसानों के लिए फसल उत्पादकता, इनपुट लागत में कमी और मौसम के जोखिम को कम करने पर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परामर्शिकाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए खास तौर पर सिर्फ़ महाराष्ट्र राज्य में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि, नेशनल काउंसिल ऑफ़ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) ने 2009, 2015 और हाल ही में 2020 में भारत के कई ज़िलों में मौसम पूर्वानुमान पर आधारित परामर्शिकाओं के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण किए थे। 2020 के अध्ययन से पता चला कि सर्वेक्षण किए गए 98% किसानों (11 राज्यों के 121 ज़िलों के 3,965 किसान) ने इन परामर्श के आधार पर नौ कृषि तरीकों में से कम से कम एक में बदलाव किया। इन बदलावों के परिणामस्वरूप, खेती करने वाले परिवारों की औसत सालाना आय में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। जिन लोगों ने सभी नौ सुझाए गए तरीकों को अपनाया, उनकी सालाना आय 1.98 लाख रुपये से बढ़कर 3.02 लाख रुपये हो गई। इससे बारिश पर निर्भर इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वर्गीकृत कृषि परिवारों के लिए सालाना आय में 12,500 रुपये की अतिरिक्त आय हुई। कुल मिलाकर, देश भर के बारिश पर निर्भर ज़िलों में अनुमानित सालाना आय में बढ़ोतरी 13,331 करोड़ रुपये रही।

(घ)–(ङ) ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के तहत कृषि मौसम विज्ञान पूर्वानुमानों के स्थानीय और डिजिटल पहुँच को बेहतर बनाने और ज़्यादा किसानों तक पहुँचने के लिए मोबाइल-आधारित प्लेटफॉर्म पर मौसम पूर्वानुमान और कृषि मौसम परामर्श को एकीकृत करने के लिए, मौसम पूर्वानुमान और कृषि मौसम परामर्श को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन, इंटरनेट, SMS जैसे मल्टीचैनल डिसेमिनेशन सिस्टम के माध्यम से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) पहलों के तहत प्रेषित किया जाता है। इसके अलावा, चक्रवात, गहरे अवदाब जैसी खराब मौसम की घटनाओं के दौरान, किसान पोर्टल के माध्यम से SMS-आधारित अलर्ट और चेतावनियाँ, साथ ही बचाव के उपयुक्त उपाय भेजे जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी प्रगति ने डिजिटल पहुँच को और गति दी है, जिससे किसान 'मेघदूत' और 'मौसम' जैसे मोबाइल ऐप और WhatsApp, Facebook जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थान के हिसाब से पूर्वानुमान और परामर्श पा रहे हैं। इसके अलावा, आईएमडी ने अपनी सेवाओं को 21 राज्य सरकारों के IT प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया है और किसान इन राज्य सरकारों के IT प्लेटफॉर्म से अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी ले रहे हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर हाल ही में पंचायत-स्तर के मौसम पूर्वानुमान लॉन्च किए हैं, जो भारत की लगभग सभी ग्राम पंचायतों को कवर करते हैं। ये पूर्वानुमान ई-ग्रामस्वराज (https://egramswaraj.gov.in), मेरी पंचायत ऐप, पंचायती राज मंत्रालय के ई-मानचित्र और भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मौसमग्राम (https://mausamgram.imd.gov.in) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

*****